

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

देहरादून: दिनांक 10 जून, 2016

विषय:-राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद के संचालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 4431/आय व्ययक-2700-II/2015-16 दिनांक 02.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1412/XVII(4)/2015/5(119)/2015 दिनांक 19.10.2015 के द्वारा किया गया है।

2. राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद के गठन के फलस्वरूप नियुक्त महानुभावों/सदस्यों को देय यात्रा भत्ता, मानदेय, टेलीफोन, व्यवसायिक सेवा तथा भवन किराया उपशुल्क का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के गठन के फलस्वरूप उक्त परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति की गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-26-राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता में धनराशि की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत धनराशि रु0 18,06,000.00/- (रु0 अठ्ठारह लाख छः हजार मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. शासनादेश संख्या 05/XVII(4)/2015-5(119)/15 TC दिनांक 05.01.2016 द्वारा राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों द्वारा जनपद में विभागवार निम्न कार्यों का अनुश्रवण किया गया है:-

1. परिषद की सदस्य, सम्बन्धित जनपद की अनुश्रवण समिति की पदेन सदस्य होंगी।
2. महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं/समस्याओं के समाधान हेतु जनपद के जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर समस्या का निदान करवाना।
3. महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं का अनुश्रवण।
4. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित योजनाओं को प्रचार-प्रसार जैसे निर्भया योजना, मा0 मुख्यमंत्री सतत योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना, नन्दा देवी कन्या योजना (हमारी कन्या हमारा अभिमान)
5. जनपद के अति कुपोषित बच्चों को टैग किया जाना, जिससे कि उन बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया जा सके।

6. विधवा/वृद्ध महिलाओं की पेंशन की स्थिति का अनुश्रवण।
7. जेल में निवास कर रही महिलाओं की स्थिति का अनुश्रवण करना।
8. किशोर व किशोरियों को महिलाओं की सुरक्षा व लिंगभेद के प्रति जागरूक करना।
9. प्रदेश सरकार में महिलाओं के विकास हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
10. जनपद के समस्त आईटीआई/पॉलिटेक्निक/डिग्री कॉलेज/जीओआईसी/ हाई स्कूल/इंटरकॉलेज/प्रावि0 में उनकी सुविधाओं के सम्बन्ध में भ्रमण करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
11. महिला अस्पतालों का भ्रमण कर उनकी समस्याओं का समाधान करना एवं सुझाव देना।
12. बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास हेतु प्रयास करना तथा बलात्कार सम्बन्धी केस जो कोर्ट में चल रहे हों, उनकी प्रगति से अवगत करवाना।

4. **वित्तीय प्रबन्धन:-** राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद में अभिलेखों का रख रखाव एवं वित्तीय प्रबन्धन आईसीडीएस के अन्तर्गत किया जायेगा। इस हेतु अलग से कैशबुक बनाई जायेगी जिसमें प्राप्त धनराशि का नियमानुसार किया जायेगा साथ ही इससे सम्बन्धित बिल बाउचर पत्रावली, स्टॉक पंजिका एवं वितरण पंजिका अलग से बनाई जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह ध्यान में रख जायेगा।

5. अग्रिम रूप से आहरित धनराशि का समायोजन कोषागार को नियमानुसार किया जायेगा इस हेतु व्यय धनराशि का नियमानुसार ऑडिट हेतु समस्त वित्तीय अभिलेख नियमित रूप से विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण किया जायेगा।

6. **वित्त की व्यवस्था:-** राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के गठन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के शेष 03 माह (जनवरी, फरवरी, मार्च) के यात्रा भत्ता, मानदेय, टेलीफोन, व्यवसायिक सेवा तथा भवन किराया उपशुल्क का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग धनराशि रु0 18,06,000.00 का व्यय अनुमानित है।

7. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
2. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड v भाग-1 के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।
3. इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30.03.2013 तथा उत्तराखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यकत व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों में करा दी जायेगी।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक 8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा-201-समेकित निधि के विनियोजन एवं अन्ततः अनुदान संख्या 15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण- 103-महिला कल्याण-26-राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद के मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28-3-2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में WWW.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 S1606990018 दिनांक 06-06-2016 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

9. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 129(p)/XXVII(1)/ 2016-17 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 129/ रा0आ0नि0/XXVII(1)/2014 दिनांक 03 जून, 2016

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
(अभिषेक स्वामी)
अपर सचिव

संख्या- 1374(1)/XVII(4)/2014/129/06TC तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
2. सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, (साइबर ट्रेजरी) 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-1/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(माध्यावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, ICDS (S022)

आवंटन पत्र संख्या - 1334/XVII(4)/2016-5(119)/15

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - S1606990018

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Jun-2016

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

HOD Name - Director I C D S (4166)

खा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

प्रसंग 103 - महिला कल्याण

26 -

मायोजन होता 00 -

(अनुदान संख्या - 015)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1806000	1806000
	0	1806000	1806000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1806000

मायावती
(मायावती ढकरीयाल)
संयुक्त सचिव।